

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 593]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर 2017—कार्तिक 10, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2017

क्र. 17180-233-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ६ सन् २०१७.

## मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१७

[“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक १ नवम्बर, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

चूंकि, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

## संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक २३ सन्  
१९५६ तथा  
अधिनियम क्रमांक  
३७ सन् १९६१ का  
अस्थाई रूप से  
संशोधित किया  
जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) धारा ३ से ४ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्वधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

## भाग-एक

## मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

## (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक २३ सन्  
१९५६ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा ३०१ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(५) ऐसे मामलों में, जहां रजिस्ट्रीकृत तथा प्राधिकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर द्वारा धारा २९४ की उपधारा (५) के उपबंधों के अनुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां ऐसे वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर, कानूनी उपबंधों तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात्, ऐसे भवन के लिए पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त होंगे. इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति आयुक्त को उसके कार्यालय में सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी.”

## भाग-दो

## मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

## (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक ३७ सन्  
१९६१ का संशोधन.

४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा १९१ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(३) ऐसे मामलों में, जहां रजिस्ट्रीकृत तथा प्राधिकृत वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर द्वारा धारा १८७ की उपधारा (३क) के उपबंधों के अनुसार भवन अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां ऐसे वस्तुविद् या संरचना इंजीनियर, कानूनी उपबंधों तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात्, ऐसे भवन के लिए पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा जारी करने हेतु सशक्त होंगे. इस उपधारा के अधीन जारी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा अधिवासित करने की अनुज्ञा की एक प्रति परिषद् कार्यालय में सात दिन के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी.”

भोपाल :

तारीख ३१ अक्टूबर, २०१७

ओ. पी. कोहली

राज्यपाल

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2017

क्र. 17180-233-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE  
No. 6 of 2017

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI  
(SANSHODHAN) ADHYADESH, 2017

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1<sup>st</sup> November 2017.]

Promulgated by the Governor in the sixty-eighth year of the Republic of India.

**An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2017. **Short title.**

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) shall have effect subject to the amendments specified in Section 3 to 4. **Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 and Act No. 37 of 1961 to be temporarily amended.**

#### PART-I

#### AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION

#### ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

3. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 301, after sub-section (4), the following new sub-section shall be added, namely :— **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.**

- "(5) In respect of cases, where building permission has been granted as per the provisions of sub-section (5) of Section 294, by the registered and authorised architect or structural engineer, such architect or structural engineer shall be empowered to issue completion certificate and permission to occupy for such building after ensuring the compliance of statutory provisions and conditions of building permission. The copy of completion certificate and permission to occupy issued under this sub-section shall be provided to the Commissioner at his office within seven days."

## PART-II

### AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961

(NO. 37 OF 1961)

Amendment to  
the Madhya  
Pradesh Act No.  
37 of 1961.

4. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in Section 191, after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely :—

- "(3) In respect of cases, where building permission has been granted as per the provisions of sub-section (3A) of Section 187, by the registered and authorised architect or structural engineer, such architect or structural engineer shall be empowered to issue completion certificate and permission to occupy for such building after ensuring the compliance of statutory provisions and conditions of building permission. The copy of completion certificate and permission to occupy issued under this sub-section shall be provided to Council at his office within seven days."

BHOPAL :

Dated, the 31<sup>st</sup> October, 2017.

O. P. KOHLI  
Governor  
Madhya Pradesh.